



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 25 मई, 2024 ई० (ज्येष्ठ 04, 1946 शक संवत्) [संख्या 21

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	381-394	3075	भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	505-512	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	..	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	87-100	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	425-439	975
			स्टोर्स-पर्वज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह (गोपन) विभाग

अनुभाग-3

अधिसूचना

26 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 I/548537/I/548538/2024-सी0एक्स0-3—चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश से पनकी, कानपुर टर्मिनल तक पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों, डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति के लिए किया जाता है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद-258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा-3 की उपधारा (2) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची**प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश**

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड गाटा संख्या-313/2 वाल्व स्टेशन-08, ग्राम-ऐर, तहसील एवं परगना-उरई, जिला-जालौन, उत्तर प्रदेश।

पूर्व में	गाटा संख्या-313/2 का शेष भाग, रमेश महेश्वरी और अन्य।
पश्चिम में	गाटा संख्या-313/2 का शेष भाग, रमेश महेश्वरी और अन्य।
उत्तर में	गाटा संख्या-313/2 का शेष भाग, रमेश महेश्वरी और अन्य।
दक्षिण में	उरई से ऐर रोड़ गाटा संख्या-316, 317

आज्ञा से,
ए0 वी0 राजामौलि,
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. I/548538/2024-CX-3, dated April 26, 2024 for general information :

NOTIFICATION*April 26, 2024*

No. I/548537 / I/548538 / 2024-CX-3—WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supplying petroleum products, diesel/petrol from Bina Refinery, Madhya Pradesh to Panki, Kanpur Terminal through Pipeline :

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification No. S.O. 1285 dated 04th May, 1963, published in Part-II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963 the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the schedule given below to be a "Prohibited Place" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this Notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE**Name and specifications of the prohibited place.**

Bharat Petroleum Corporation Limited Gata No. 313/2 Valve Station-08, Village-Air, Tehsil and Pargana-Orai, District-Jalaun, Uttar Pradesh.

<i>In East</i>	Remain Part of Gata No. 313/2, Ramesh Maheshwari And other.
<i>In West</i>	Remain Part of Gata No. 313/2, Ramesh Maheshwari And other.
<i>In North</i>	Remain Part of Gata No. 313/2, Ramesh Maheshwari And other.
<i>In South</i>	Orai to Air Road, Gata No. 316, 317.

By order,
A. V. RAJAMAULI,
Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 181/एक-14/2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला-गाजियाबाद के 102 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम
1	2	3
गाजियाबाद	मोदीनगर	सुराना, पूठरी, आसिफपुर उजैड़ा, फतेहपुर, बन्दीपुर, शहजादपुर, नेकपुर साबितनगर, विहंग, रेवड़ी रेवड़ा, मानौली, रो.स.बाद पट्टी जीराम, सरना मुरादनगर, मौहम्मदपुर धेदा, काजमपुर, कादराबाद, शाहजहाँपुर, मछरी, जैनुद्दीनपुर, बेगमाबाद बुदाना(अंदर), भोजपुर, कलछीना, युसुफपुर ईसापुर, जोया, औरंगाबाद दतैड़ी, अब्दुल्लापुर दतैड़ी, सीकरी कलां, औरंगाबाद गदाना, बिसोखर, बेगमाबाद बुदाना (बाहर), उखलारसी, निवाड़ी देहात, पतला देहात।
“	गाजियाबाद	मकरमतपुर सिकरोड, मथुरापुर, नंगला फिरोज मोहनपुर, अटौर, मिस्वापुर, डासना, कुशलिया, करीमनगर कटियार उर्फ आकलपुर, महीउद्दीनपुर ढबारसी, खोड़ा, अकबरपुर बहरामपुर, अर्थला, कैला, कड़कड़ माडल, करहैड़ा, घूकना, चिकम्बरपुर, जगौला, जटवाड़ा कलां, झण्डापुर, डूण्डा हेड़ा, नासरपुर, प्रहलादगढ़ी, ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, बोहन्जा, मकनपुर, मवई, महमासराय उर्फ कोट, महाराजपुर, मेवला अगरी, शाहबाद उर्फ मीठेपुर, सद्दीकनगर, सिहानी, साहिबाबाद, महरौली, रईसपुर, शाहपुरबम्हैटा, सदरपुर, हरसाऊँ, ढरगल, मोरटा, पसौन्डा, मकरमतपुर, हसनपुर भोवापुर, मिर्जापुर, लालपुर, सिकन्दरपुर, रजापुर, महीउद्दीनपुर कनवानी।
“	लोनी	बदरपुर, सादाबाद डुगरावली, दौलताबाद भोवापुर, जाफराबाद गनौली, धारीपुर, चिरौड़ी, फतियाबाद निठौरा, शकरपुला, कोतवालपुर, सिरौरा सलेमपुर, मुर्तजाबाद भूपखेड़ी, अहमदनगर नयाबांस, औरंगाबाद रिस्तल, अफजलपुर, निस्तौली, पावी सादकपुर, धरोटी खुर्द, बहटा हाजीपुर, लोनी (चकबंदी बाहरी), सादुल्लाबाद, अहमदनगर नवादा।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT**SECTION -14**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 181/1-14/2022**, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 181/1-14/2022—In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U. P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 102 Villages of District Ghaziabad specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village
1	2	3
Ghaziabad	Modinagar	Surana, Puthri, Asifpur Ujaira, Fatehpur, Bandipur, Shahzadpur, Nekpur Sabitnagar, Bihang, Rewadi Revda, Manauli, Roshanpur Salaimabad Patti Jiram, Sarna Murad Nagar, Mohammadpur Dheda, Kajampur, Kadrabad, Shahjahanpur, Machhri, Zainuddinpur, Begamabad Budana (Andar), Bhojpur, Kalchhina, Yusufpur Isapur, Joya, Aurangabad Dateri, Abdulapur Dateri, Sikri Kalan, Aurangabad Gadana, Bisokhar, Begumabad Budana (Bahar), Ukharsa, Niwari Dehat, Patla Dehat.
Do.	Ghaziabad	Makmatpur Sikrod, Mathurapur, Nagla Firoj Mohanpur, Aatur, Miswapur, Dasna, Kushaliya, Karimnagar Katihar <i>urf</i> Akalpur, Mahiuddinpur Dhabarsi, Khora, Akbarpur Bahampur, Arthala, Kaila, Karkar Modal, Karhera, Ghukna, Chikambarpur, Jagola, Jatwara Kalan, Jhandapur, Dundaheda, Nasarpur, Prahlad Garhi, Brahampur <i>urf</i> Bhopura, Bohnja, Makanpur, Mavai, Mahmasarai <i>urf</i> Kot, Maharajpur, Mevla Agri, Shahbad <i>urf</i> Mithhepur, Saddiknagar, Sihani, Sahibabad, Mehroli, Raispur, Shahpur Bemheta, Sadarpur, Harsaon, Dhargal, Morta, Pasonda, Makramatpur, Hasanpur Bhowapur, Mirzapur, Lalpur, Sikandarpur, Razapur, Mahiuddinpur Kanawani.
Do.	Loni	Badarpur, Sadabad Dugraoli, Daultabad Bhowapur, Jafarabad Ganauli, Dharipur, Chirauri, Fatiyabad Nithora, Shakar Pulla, Kotwalpur, Sirora Salempur, Murtazabad Bhoopkheri, Ahmadnagar Nayabans, Aurangabad Ristal, Afzalpur, Nistauli, Pavi Sadakpur, Dharoti Khurd, Behta Hazipur, Loni (Chakbandi Bahar), Sadullabad, Ahmadnagar Nawada.

By order,
Manoj Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 182/एक-14/2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला-गौतमबुद्धनगर के 77 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम
1	2	3
गौतमबुद्धनगर	दादरी	युसुफपुर (चकसाबेरी), दुजाना, महावड, देवला, तिलपता करनवास, चौना, नंगला किरानी, आमका, गुलावठी खुर्द, जारचा, छलैरा खादर, छलैरा बांगर, नौरगांवा खादर, रायपुर खादर, सदरपुर, हाजीपुर, छजारसी।
„	गौतमबुद्धनगर	नगलीनगला, नगली वहरामपुर, मंगरौला, नगली शाकपुर, चक मंगरौला, किडावली, दोस्तपुर मंगरौली खादर, दोस्तपुर मंगरौली बांगर, याकूतपुर द्वितीय, दलेलपुर, गुलावली, डाढा, कौडलीखादर, कामवख्शपुर, औरंगाबाद, गढ़ी समस्तपुर, घरबरा, तिलवाड़ा, मुरशदपुर, मोतीपुर, जगनपुर दोआवा, देवटा, विलासपुर, बागपुर, ननुवा का राजपुर, अट्टा गुजरान, दनकौर देहात, औरंगपुर, वेला खुर्द, वेला कला, लतीफपुर खादर, मकनपुर खादर, भट्टा, कासना, कुलेसरा, लखनावली, वाजिदपुर, शहदरा, सुथियाना।
„	जेवर	रबूपुरा, तकीपुर बांगर, तकीपुर खादर, महेन्दीपुर खादर, महेन्दीपुर बांगर, भीकनपुर, अमर पुर पलाका, फलैदा खादर, करौली खादर, बल्लभनगर उर्फ करोल खादर, रामपुर खादर, सिरसा, माछीपुर बांगर, माछीपुर खादर, गोविन्दगढ, मीरपुर कच्छ उर्फकानी गढी, शमशमनगर, झुप्पा, अलियाबाद उर्फ महेन्दीपुर, अहमद पुर चौरौली, जहांगीर पुर।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT**SECTION -14**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 182/1-14/2022**, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 182/1-14/2022—In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 77 Villages of District Gautambudha Nagar specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village
1	2	3
G. B. Nagar.	Dadri	Yusufpur Chak Saberi, Dujana, Mahamvad, Devla, Tilpata Karanwas, Chauna, Nagla Kirani, Arnka, Gulaothi Khurd, Jarcha, Chhalaera khadar, Chhalaera bangar, Naurangabad khadar, Raipur khadar, Sadarpur, Hajipur, Chhajarsi.
Do.	Gautam Budhanagar.	Nagla Nagli, Nagli Bahrapur, Mangrola, Nagli Shakpur, Chak Mangrola, Kidawali, Dostpur Mangroli Khadar, Dostpur Mangroli Bangar, Yakootpur Dalelpur, Gulavali, Dadha, Kondli Khadar, Kambakashpur, Aurangabad, Gari Samastpur, Gharbarah, Tilwara, Murshadpur, Motipur, Jaganpur Doab, Deota, Vilaspur, Bagpur, Nanua Ka Razapur, Atta Gujran, Dankaur, Aurangpur, Bela Khurd, Bela Kalan, Latifpur Khadar, Makanpur Khadar, Bhatta, Kasna, Kulesra, Lakhnavali, Wajidpur, Shahdara , Suthiyana.
Do.	Jewar	Rabupura (Rural), Taquipur Bangar, Taquipur Khadar, Mahadipur Khadar, Mahadipur Bangar, Bhikanpur, Amarpur Palaka, Falaida Khadar, Karauli Khadar, Ballabh Nagar <i>urf</i> Karaulkhadar, Rampur Khader, Sirsa, Machhipur Bangar, Machhipur khadar, Govindgarh, Mirpur Kachh <i>urf</i> Kanigarhi, Shamsham Nagar, Jhuppa, Aliyabad <i>urf</i> Mandipur, Ahmadpur Choroli, Jahangirpur.

By order,
Manoj Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 183/एक-14/2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला-बुलन्दशहर के 32 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम
1	2	3
बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद	ककोड टाउन, सिकन्द्राबाद देहात, बिलसूरी, जाहिदपुर, सिकन्द्राबाद अ0न0पा0क्षेत्र।
“	बुलन्दशहर	औरंगाबाद, धमैडा कीरत, कस्वा वरन बाहर, वहलीमपुरा, मीरपुर, गुलाबटी देहात, वरन अन्दर नगरपालिका।
“	स्याना	स्याना (टाउन एरिया), खाद मौहननगर।
“	अनूप शहर	जहांगीराबाद, मुवारकपुर, अकबरपुर उर्फ वच्चीखेडा खादर, अनूपशहर बाँगर।
“	डिबाई	दौका, डिबाई देहात, कर्णवास खादर, औरंगाबाद कसेर, नौदई खादर, निवाड़ी खादर, रामघाट बांगर, डिबाई शहरी।
“	शिकारपुर	खेलिया कल्यानपुर, छतारी अन्दर टाऊन।
“	खुर्जा	नगलिया टक्कर, हीरापुर नगला जगत, ठेगौरा, खुर्जा अन्दर चुंगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT**SECTION -14**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 183/1-14/2022**, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 183/1-14/2022—In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 32 Villages of District Bulandshahar specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village
1	2	3
Bulandshahar	Sikandrabad	Kakor, Sikandrabad Rural, Bilsuri, Zahidpur, Sikandrabad Urban.
Do.	Bulandshahar	Aurangabad, Dhamera Kirat, Bulandshahar Dehat, Bahalimpura (CT), Meerpur, Gulaothi Rural, Baran City.
Do.	Syana	Siyana, Khad Mohan Nagar.
Do.	Anupshahar	Jahangirabad Rural, Mubarikpur, Akbarpur <i>urf</i> Bachchikhera Khad, Anoopshahr Bangar.
Do.	Debai	Dauka, Dibai (Dehat), Karnvas Khadar, Aurangabad Kasair, Naudai Khader, Niwari Khader, Ramghat Bangar, Dibai Urban.
Do.	Shikarpur	Khailia Kalyanpur, Chatari.
Do.	Khurja	Nagalia Takkar, Hirapur Nagla Jagat, Thangora, Khurja City.

By order,
Manoj Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 184/एक-14/2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला-अलीगढ़ के 173 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम
1	2	3
अलीगढ़	खैर	घरबरा, फाजिलपुर कच्छ, टप्पल, हीरपुरा, उटवारा, बझेडा, महगौरा, धर्मपुर, उदयगढी, वाजीदपुर, खैर।
“	गभाना	धर्मपुर, डेटा सैदपुर, बाहरपुर, जोहरा, भगतपुर, थानपुर खानपुर, चांदनेर, आरामगढी, नबाबपुर, नूरुल्लापुर, ग्वालरा, घौरोट, बसई, अकरावत, राजमऊ, आराजीजंगल, गोलगढी, माधौगढ़, रामनगर, पोकलगढी, बरौली, खुर्दखेड़ा, फरीदपुर, बाजगढी, ओरिहा, रफीपुरसिया।
“	अतरौली	जामुना, काजिमाबाद, शेखूपुर, बैमबीरपुर, जिरौली धूमसिंह, बैजला, रजातऊ सेऊपुर, बिरनेर, गिजरौली, गाँवखेड़ा, नगला निजाम, पैड़रा, आलीपुर, टोडरपुर अहतमाली (गैरआबाद), गनेशपुर गंग (गैरआबाद), गंगाबास, फतहपुर गंग (गैरआबाद), किरतौली, हारूनपुर अहतमाली, हारूनपुर गैर अहतमाली, नगाबली शकूरगंज, हैबतपुर कोटरा, धुरा टोडकपुर, तोछी, कल्यान नगर, बिजौली, अटा, बाबूपुर, दहेली, अभयपुरबहलोलपुर, अजमानढेर, नबीपुर, सिकन्दरपुर, मझोला, अतरौली पट्टी नजफ खाँ बाहरचुंगी, नगलिया अशरफाबाद, अतरौली पट्टी शेरसिंह अंदरचुंगी, छर्ना टाउन, धनसारी (टाउन एरिया)।
“	कोल	महराबल, इलियासपुर महरावल, खेड़ा खुशखबर, लेखराजपुर, बरौला जाफराबाद, केसोपुर जोफरी, करीलिया, पीजरी नागरी, बिनूपुर, शहरी मदनगढी, अहमदपुर उम्मरखाँ, ऐसी, कस्बा कोल-1, हाजीपुर चोहट्टा, रुस्तमपुर सकतखाँ, मनोहरपुर कायस्थ, नगला भाईबेग, चिलकौरा, तालसपुर कला, भगनपुर, सूरजपुर, शिकारगढी, सुनामई, चारुपुर, रठगवाँ, हैबतपुर सिया, मिर्जापुर सिया, आलमपुर सुबकरा माफी, सिकन्दरपुर छेरत, रसूलपुर देवसेनी, किढ़ारा, उखलाना, खेड़ा. बुर्जुग, चेंडौली खुर्द, मीरपुर, शाहपुर, बरकातपुर, खान आलमपुर, निधौला, छिड़ावली, विसावनपुरसिल्ला, दौलतपुर, ईकरी, पनैटी, याकूतपुर, पिखलौनी, बोनर, धीरध रपुरगढियावली, चिरौलीदाउदखाँ, कोछोड़, घासीपुर, दिहौली, कासिमपुर, दभौरा, गोवर्धनपुर, जुझारपुर, दभा, मंडनपुर, सल्लपुरा (गैर आबाद), कूआगाँव, गोपालपुर (गैर आबाद), टुआमई, राजीपुर, सुहावली, दुभिया, बरौठा, गम्भीरपुरा,

1	2	3
अलीगढ़	कोल	सारसौल (अंदर चुंगी), अशरफपुर जलाल, रामपुर, मन्जूरगढ़ी, धौरा माफी, पिलखना, किशनपुर, जमालपुर माफी, जलाली-1, जलाली-2, बेगपुर कन्जौला, भमौला माफी, साहिबाबाद पला, पला साहिबाबाद अन्दरचुंगी, मुल्लापाड़ा भुजपुरा, रसूलपुर स्वाद कस्बा, कस्बा कोल-2, सारसौल (बाहर चुंगी), हरदुआगंज(बाहर चकबंदी, भमौला छावनी।
“	इगलास	नगला कलुआ बैलौठ, लखटोई, रामनगर, महुआ, जारौठ, नगला चूरा, कजरौठ, तरसारा, नया बास, साथिनी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

SECTION -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 184/1-14/2022**, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 184/1-14/2022—In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 173 Villages of District Aligarh specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village
1	2	3
Aligarh	Khair	Gharvara, Fazilpur Kachh, Tappal, Hirpura, Utwara, Bajhera, Mahgaura, Dharmpur, Udai Garhi, Vajidpur, Khair.
Do.	Gabhana	Dharmpur, Deta Saidpur, Baharpur, Johra, Bhagatpur, Thanpur Khanpur, Chandner, Aramgarhi, Navabpur, Noorullapur, Gwalara, Ghoroth, Basai, Akrvat, Rajmau, Araj Jangal, Gol Garhi, Madho Garh, Ramnagar, Pokhar Garhi, Barauli, Khurd Khera, Faridpur, Bajgarhi, Orha, Rafipur Siya.

1	2	3
Aligarh	Atrauli	Jamuna, Kazimabad, Shekhupur, Baimbirpur, Jirauli Dhoom Singh, Baijla, Rajatau Seupur, Birner, Gijrauli, Gaon Khera, Nagla Nizam, Pendra, Alipur, Todarpur Ahatmali, Ganeshpur Gang, Gangabas, Fatehpur Gang, Kirtoli, Haranpur Ahatmali, Haranpur Gair Ahatmali, Nagavali Shakurganj, Haivatpur Kotra, Dhurra Todarpur, Tochhi, Kalyan Nagar, Bijauli, Ata, Babupur, Daheli, Abhaypur Bahlolpur, Ajvaman Dher, Nabipur, Sikanderpur, Majhaura, Arauli Patti Najaf Khan Bahar Chungi, Nagaliya Ashrafabad, Patti Sher Singh (Atrauli), Chharra Town, Dhansari (Town Area).
Do.	Koil	Mahrawal, Ilyaspur Mahrawal, Khera Khus Khabar, Lekhrampur, Baraula Jafrabad, Keshopur Jophri, Karilia, Pinjri Nagri, Binupur, Shaharimadan Gari, Ahamadpur Ummarkhan, Aisi, Kasba Koil-1, Hajipur Chauhatta, Rustampur Sakatkhan, Manoharpur Kayastha, Nagla Bhaibeg, Chilkaura, Talasपुर Kalan, Bhaganpur, Soorajpur, Sikargarhi, Sunamai, Chaupur, Rathgawan, Haivatpur Siya, Mirzapur Siya, Alampur Subkaramafi, Sikandrapur Cherat, Rasoolpur Devsaini, Kithara, Ukhlana, Khera Buzurg, Chairauli Khurd, Meerpur, Shahapur, Barkatpur, Khan Alampur, Nidhaura, Chhiravali, Bisavanpur Silla, Daulatpur, Ikari, Panaiti, Yakutpur, Pikhlauni, Boner, Dhirdharpur Gadiyawali, Chirauliya Daudkhan, Kochhor, Ghasipur, Dihauli, Qasimpur, Dabhaura, Govardhanpur, Jujharpur, Dabha, Mandanpur, Sallpura gair abad, Kuwagaon, Gopalpur gair abad, Tuamai, Rajipur, Suhawali, Dubhiya, Barautha, Gambhirpura Dehat, Sarsaul (Andar chungi), Ashrafpur Jalal (CT), Rampur (CT), Manjoor Garhi (CT), Dhaurra Mafi (CT), Pilkhana, Kisanpur, Jamalpur Mafi, Jalali-1, Jalali-2, Begpur Kanjoula, Bhamola Mafi, Sahibabad Pla, Pla Sahibabad Ander, Mullapada Bhujpura Andar Chungi, Rasoolpur Swad Kasba, Kasba Koil-2, Sarsaul (Bahar Chungi), Harduaganj (Bahar Chakbandi), Bhamola Chhawani.
Do.	Iglas	Nagla Kalua Bailauth, Lakhtoi, Ramnagar, Mahoa, Jarauth, Naglachura, Kajroth, Tarasara, Nayabas, Sathini.

By order,
Manoj Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 185/एक-14/2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला-हाथरस के 65 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम
1	2	3
हाथरस	सासनी	ऊसवा, सासनी देहात, रुदायन, लुटसान, सलेमपुर।
“	सिकन्दराऊ	मीरपुर, नाईनगला ताहर, खिजरपुर, वढानू, कचौरा, खेडिया टप्पा अगसौली, अगसौली, खिजरपुर कस्बा, अरनिया तलेसरा, गन्थरी शाहपुर, ठाठपुर गैर आबाद, इकबालपुर, खेडिया खुर्द, अगराना जरारा, जाऊ इनायतपुर, जहांगीर पुर कौंडरा, खेडिया कला फुलरई, मुगलगढी, अमृतपुर असदपुर, अजमतपुर अजगरा, जनसोई, असोई, गडोला, नगला कौंच, गौपाल पुर, खिटौली, नगला पार, छीतूपुर, ज्ञानपुर, गढी वीरवल, कानऊ, सि0राऊ अन्दर चुंगी।
“	हाथरस	बरामई, कुरार, रमनपुर, खोडा हजारी, अल्हैपुर चुरसैन, कूवरपुर नगला बांस, नगला रामराय, बर्दवारी, महमूदपुर जाटान, नगला बिहारी देह माफी, हाथरस देहात, नवीनपुर, मुरसान, बालापट्टी अढईया, बालापट्टी सेख जाफर, गढीमधू, नगला जोधा, मैडू, यहियापुर, बाला पट्टी शेख जाफर बा0चुं0, हतीसा भगवन्तपुर बा0चुं0, गढी कंधारी।
“	सादाबाद	मडनई, नौपुरा, औराजी मिल्क कूपा, नगला मौजी, रुदायल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT**SECTION -14**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 185/1-14/2022**, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 185/1-14/2022—In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 65 Villages of District Hathras specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village
1	2	3
Hathras	Sasni	Uswa, Sasni Dehat, Rudayan, Lutsan, Salempur.
Do.	Sikandara Rao	Mirpur, Nai Naglatahar, Kizerpur, Badhanoo, Chhonkara, Kheria Tappa Agsauli, Agsauli, Khijarpur Qasba, Arnia Talesra, Ganthari Shahpur, Thathpur, Ikbalpur, Kheria Khurd, Agrana Jarara, Jauinayatpur, Jahangirpur Kondra, Kheria Kalan, Phulrai Mughal Garhi, Amritpur Asadpur, Azmatpur Ajgara, Jansoi, Asoi, Garhaura, Nagla Kanch, Gopalpur, Khिताuli, Naglapar, Chhitupur, Gyanpur, Garhi Birbal, Kanau, Sikandrarao ander Chungi.
Do.	Hathras	Baramai, Kurar, Ramanpur, Khonda Hajari, Allahpur Chursen, Kumarpur Nagla Bans, Nagla Ramrai, Bardwari, Mehmudpurjatan, Nagla Bihari Deh Mafi, Hathras Dehat (CT), Navipur, Mursan, Balapatti Adaiya, Bala Patti Sekh Jafar, Garhi Madhu, Nagla Jodha, Medu, Yahiyapur, Bala Patti Sekh Jafar Bh.Ch., Hatisha Bh.Ch., Garhi Kandhari.
Do.	Sadabad	Madnai, Naupura, Araj Milk, Kupa, Nagl Mauji, Rudail.

By order,
Manoj Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 मई, 2024 ई० (ज्येष्ठ 04, 1946 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

18 जून, 2022 ई०

सं० 201/सात-भू०सु०-2022-शासनादेश संख्या-68/3-2(6)/79 रा०-1 दिनांक 01 जुलाई, 1983 एवं अद्यतन शासनादेश-985/एक-1/2011-12(23)/2006-141 दिनांक 30 अगस्त, 2011 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र० राजस्व संहिता, 2016 की धारा-59(4) ग एवं नियमावली के नियम-55 के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना सं०-258/रा०-1-16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम सं०-6/7 में उल्लिखित गाटा सं०-313ख रकबा-0.607 हे० व गाटा सं०-311 रकबा-0.227 हे० कुल 02 गाटा रकबा-0.834 हे० भूमि का पुनर्ग्रहण बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु उ०प्र०, पर्यटन विभाग को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	अजईपुर	313ख (भूदान समिति) श्रेणी-1 311 (बंजर) श्रेणी-5-3-ड	0.834 हे०	उ०प्र०, पर्यटन विभाग (बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु)

सं0 202/सात-भू0सु0-2022-शासनादेश संख्या-68/3-2(6)/79 रा0-1 दिनांक 01 जुलाई, 1983 एवं अद्यतन शासनादेश-985/एक-1/2011-12(23)/2006-141 दिनांक 30 अगस्त, 2011 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2016 की धारा-59(4) ग एवं नियमावली के नियम-55 के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना सं0-258/रा0-1-16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 व सं0-258/16(1)-1973-राज-1 दिनांक 16 जून, 1981 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम सं0-7/8 में उल्लिखित गाटा सं0-920 मि0 कुल गाटा-7 आ0नं0 920ग, 920ड़, 920च, 920छ, 920ज, 920ट, 920ठ कुल क्षेत्रफल 1.999 हे0 वर्गमीटर बंजर भूमि को राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु उ0प्र0, आयुष विभाग को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट संख्या/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	रामपुर	920 मि0 कुल गाटा-7 आ0नं0 920ग, 920ड़, 920च, 920छ, 920ज, 920ट, 920ठ	1.999 हे0 बंजर भूमि	उ0प्र0, आयुष विभाग (राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु)

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी, वाराणसी।

10 मार्च, 2023 ई0

सं0 490/सात-भू0सु0-2023-शासनादेश संख्या -32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस0 राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में

लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ०नं०-1419 मि० रकबा 0.595 हे० को एन०सी०डी०सी० ब्रांच/बी०एस०एल०-3 लैंब की स्थापना हेतु चिकित्सा विभाग को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	रामपुर	आ०नं० 1419 मि०	0.595 हे० बंजर	चिकित्सा विभाग (एन०सी०डी०सी० ब्रांच/ बी०एस०एल०-3 लैंब के निर्माण हेतु)

16 मार्च, 2023 ई०

सं० 502/सात-भू०सु०-2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ०नं०-938 रकबा 0.024 हे०, आ०नं०-1017 रकबा 0.038 हे०, आ०नं०-1043 रकबा 0.024 हे०, आ०नं०-1046 रकबा 0.024 हे०, आ०नं०-1047 रकबा 0.040 हे० (नाली) तथा आ०नं०-1003 रकबा 0.012 हे०, आ०नं०-1049 रकबा 0.032 हे० (चकमार्ग) व आ०नं०-943 रकबा 0.069 हे० आ०नं०-1022 रकबा 0.175 हे० भूमि (मुख्यमार्ग) अर्थात् कुल योग 09 गाटा रकबा 0.440 हे० भूमि को अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हेतु खेल विभाग, उ०प्र० सरकार को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	राजातालाब	कसवार राजा	गंजारी	कुल गाटा-9 आ०नं० 938, 1017, 1043, 1046, 1047, 1003, 1049, 943, 1022	0.440 हे०	खेल विभाग, उ०प्र० सरकार (अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु)

23 जून, 2023 ई०

सं० 949/सात-भू०सु०-2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ०नं०-1083 रकबा 0.0570 हे० बंजर भूमि में से 0.0240 हे० भूमि को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	सदर	कटेहर	रौनाकला	आ०नं० 1083 बंजर भूमि	0.0240 हे०	आयुष विभाग (राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु)

सं० 950/सात-भू०सु०-2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ०नं०-622/8 रकबा 0.255 हे० बंजर भूमि में से 2000 वर्गफीट भूमि को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	सदर	कटेहर	राजवाड़ी	आ०नं० 622/8 बंजर भूमि	2000 वर्गफीट	आयुष विभाग (राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु)

सं० 951/सात-भू०सु०-2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित कुल गाटा-1 आ०नं०-613 रकबा 0.263 हे० में से 0.0186 हे० अर्थात् 2000 वर्गफीट नवीन परती भूमि को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
हेक्टेयर							
1	वाराणसी	पिण्डरा	कटेहर	महगांव	आ०नं० 613 नवीन परती	0.0186 हे०	आयुष विभाग (राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु)

सं० 952/सात-भू०सु०-2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ०नं०-61/608 रकबा 0.1500 हे० बंजर भूमि में से 0.0110 हे० भूमि को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
हेक्टेयर							
1	वाराणसी	सदर	जाल्हूपुर	गोबरहा	आ०नं० 61/608 बंजर भूमि	0.0110 हे०	आयुष विभाग (राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु)

सं0 953/सात-भू0सु0-2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस0 राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ0नं0-886ख रकबा 0.0610 हे0 बंजर भूमि में से 0.0220 हे0 भूमि को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	सदर	कसवार राजा	कोटवा	आ0नं0 886ख बंजर भूमि	0.0220 हे0	आयुष विभाग (राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु)

सं0 954/सात-भू0सु0-2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस0 राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित कुल गाटा-1 आ0नं0-984 रकबा 0.0280 हे0 में से 0.011 हे0 बंजर भूमि को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	सदर	जाल्हूपुर	सीवों	आ0नं0 984 बंजर	0.011 हे0	आयुष विभाग (राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु)

सं० 955/सात-भू०सु०-2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित कुल गाटा-1 आ०नं०-1181 रकबा 0.43 डि० में से रकबा 1200 वर्गफीट आबादी भूमि को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	सदर	कटेहर	कैथी	आ०नं० 1181 आबादी	1200 वर्गफीट	आयुष विभाग (राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु)

30 जून, 2023 ई०

सं० 959/सात-भू०सु०-2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित कुल गाटा-1 आ०नं०-624 रकबा 0.061 हे० बंजर भूमि को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	पिण्डरा	पन्द्रह	अनेई	आ०नं० 624 बंजर	0.061 हे०	आयुष विभाग (राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु)

25 नवम्बर, 2023 ई०

सं० 1263/सात-भू०सु०-2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित गाटा सं०-मि० 31 रकबा-2.3350 हे० में से 1.0200 हे० व गाटा सं०-26क्ष रकबा-1.5300 हे० में से 1.0000 हे० कुल रकबा-2.0200 हे० को राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु आयुष (होम्योपैथिक विभाग) को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	गड़खड़ा	कुल गाटा-2 गाटा सं०-मि० 31 गाटा सं०-26क्ष	2.0200 हे० बंजर (श्रेणी-5-1)	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज (आयुष विभाग)

एस० राजलिंगम,
जिलाधिकारी, वाराणसी।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, २५ मई, २०२४ ई० (ज्येष्ठ ०४, १९४६ शक संवत्)

भाग ७-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख १९ जनवरी, २०२४ ई०
२९ पौष, १९४५ (शक)

आदेश

सं० ७६/उत्तर प्रदेश-वि०स०/अलीगढ़/२०२२/सी०ई०एम०एस०-III-यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की ७१-खैर (अ०जा०) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन २०२२ अधिसूचना नं०-२८/६१-२०२२ दिनांक १४ जनवरी, २०२२ के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा-७८ के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से ३० दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः ७१-खैर (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम १० मार्च, २०२२ को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख ०९ अप्रैल, २०२२ थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक ०८ अप्रैल, २०२२ और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं०-२८७/निर्वाचन व्यय सेल/वि०स०सा०नि०-२०२२/पत्रा०-०१/२०२१ के जरिए अग्रेषित दिनांक २७ अप्रैल, २०२२ की रिपोर्ट के अनुसार श्री जगदीश प्रसाद जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन २०२२ के निर्वाचन क्षेत्र ७१-खैर (अ०जा०) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री जगदीश प्रसाद को कारण बताओ नोटिस सं0-76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री जगदीश प्रसाद को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा अपने दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या-2060/डीईओ के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या-1017/डीईओ-व्यय लेखा-2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री जगदीश प्रसाद ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जगदीश प्रसाद निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क)-निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन के अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख)-उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा-

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 71-खैर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री जगदीश प्रसाद निवासी केसी नगला, मा0-उटवारा, तहसील-खैर, जिला-अलीगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 19th January, 2024
29th Pausha, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Aligarh/2022/CEMS-III—WHEREAS, the General Election to 71-Khair (SC) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 71-Khair (SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 08 April, 2022 submitted by the District Election Officer, Aligarh, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Shri Jagdish Prasad, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 71-Khair (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Aligarh, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 14 November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Jagdish Prasad for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 14 November, 2022, Shri Jagdish Prasad was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 23 November, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Aligarh, *vide* its letter no. 2060 / डीईओ dated 27 December, 2022; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Aligarh in his Supplementary Report, *vide* its letter 1017 / डीईओ व्यय लेखा-2022 dated 18 October, 2023 has reported that Shri Jagdish Prasad has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Jagdish Prasad has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that—

"If the Election Commission is satisfied that a person—

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Jagdish Prasad resident of K.C. Nagala Utwara Tehsil-Khair, Dist.-Aligarh, a contesting candidate from 71-Khair (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 19 जनवरी, 2024 ई0
29 पौष, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/अलीगढ़/2022/सी0ई0एम0एस0-III—यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की 73-अतरौली विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 73-अतरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 08 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती अखलेश देवी, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 73-अतरौली से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती अखलेश देवी को कारण बताओ नोटिस सं0-76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती अखलेश देवी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा अपने दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या-2060/डीईओ के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या-1017/डीईओ-व्यय लेखा-2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती अखलेश देवी ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती अखलेश देवी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क)-निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख)-उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा-

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 73-अतरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती अखलेश देवी निवासी ग्राम-शेखूपुर, पोस्ट-काजिमाबाद, तहसील-अतरौली, जिला-अलीगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 19th January, 2024
29th Pausha, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Aligarh/2022/CEMS-III—WHEREAS, the General Election to 73-Atrauli Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 73-Atrauli Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 08 April, 2022 submitted by the District Election Officer, Aligarh, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Smt. Akhalesh Devi, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 73-Atrauli Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Aligarh, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated

14 November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Akhalesh Devi for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 14 November, 2022, Smt. Akhalesh Devi was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 13 December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Aligarh, vide its letter no. 2060 / डीईओ dated 27 December, 2022; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Aligarh in his Supplementary Report, vide its letter 1017 / डीईओ व्यय लेखा-2022 dated 18 October, 2023 has reported that Smt. Akhalesh Devi has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Akhalesh Devi has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that—

"If the Election Commission is satisfied that a person—

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Akhalesh Devi resident of Vill. Shekhupur, Post-Kazimabad, Tehsil-Atrauli, District-Aligarh, a contesting candidate from 73-Atrauli Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 19 जनवरी, 2024 ई0
29 पौष, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/अलीगढ़/2022/सी0ई0एम0एस0-III-यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की 71-खैर (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 71-खैर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 08 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मूलचंद जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 71-खैर (अ0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मूलचंद को कारण बताओ नोटिस सं0 -6/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मूलचंद को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा अपने दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या-2060/डीईओ के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभिकर्ता श्री विनय कुमार के भतीजे श्री कुलदीप चौधरी द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या-1017/डीईओ-व्यय लेखा-2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मूलचंद ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मूलचंद निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क)-निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख)-उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा-

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 71-खैर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मूलचंद निवासी ग्राम-हरजी की गढ़ी उर्फ गढ़ी सूरजमल, पोस्ट-खण्डेहा, जिला-अलीगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 19th January, 2024

29th Pausha, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Aligarh/2022/CEMS-III-WHEREAS, the General Election to 71-Khair (SC) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 71-Khair (SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 08 April, 2022 submitted by the District Election Officer, Aligarh, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Shri Mulchand, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 71-Khair (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Aligarh, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 14 November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Mulchand for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 14 November, 2022, Shri Mulchand was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by Shri Kuldeep Chaudhery, Nephew of the Election Agent Shri Vinay Kumar of the candidate on 23 November, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Aligarh, *vide* its letter no. 2060 / डीईओ dated 27 December, 2022; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Aligarh in his Supplementary Report, *vide* its letter 1017 / डीईओ व्यय लेखा-2022 dated 18 October, 2023 has reported that Shri Mulchand has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Mulchand has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that—

"If the Election Commission is satisfied that a person—

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Mulchand resident of Vill-Harji ki Garhi urf Garhi

Surajmal, Post-Khandeha, Dist.-Aligarh, a contesting candidate from 71-Khair (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 19 जनवरी, 2024 ई0
29 पौष, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/संतकबीरनगर/2022/सी0ई0एम0एस0-III-यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की 314-धनघटा (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-88/61-2022 दिनांक 04 फरवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 314-धनघटा (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार गिरजेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 314-धनघटा (अ0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम

(5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए गिरजेश को कारण बताओ नोटिस सं0-76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए गिरजेश को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, संत कबीर नगर द्वारा अपने पत्र संख्या-835/जि0नि0अ0/सं0क0न0 दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, संत कबीर नगर द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के पत्र संख्या-835/जि0नि0अ0/सं0क0न0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गिरजेश ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि गिरजेश निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क)—निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख)—उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा—

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 314-धनघटा (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी गिरजेश निवासी ग्राम-समदा, पोस्ट-सोनबरसा बाजार, जिला-गोरखपुर को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 19th January, 2024
29th Pausha, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Sant Kabir Nagar/2022/CEMS-III—WHEREAS, the General Election to 314-Dhanghata (SC) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 88/61-2022 dated 04th February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 314-Dhanghata (SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Girjesh, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 314-Dhanghata (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 19 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Girjesh for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 19 December, 2022, Girjesh was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 26 December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sant Kabir Nagar, *vide* its letter no. 835/जि0नि0अ0/सं0क0न0 dated 21 November, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Sant Kabir Nagar in his Supplementary Report, *vide* its letter 835/जि0नि0अ0/सं0क0न0 dated 21 November, 2023 has reported that Girjesh has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Girjesh has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that—

"If the Election Commission is satisfied that a person—

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Girjesh resident of Village-Samada, Post-Sonvarsa Bazar, Dist-Gorakhpur a contesting candidate from 314-Dhanghata (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 मई, 2024 ई० (ज्येष्ठ 04, 1946 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगर पंचायत एट, जालौन

उपविधि

11 दिसम्बर, 2023 ई०

सं० 901/न०प०एट/भ०नि०/उपविधि/2023-24-उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 298(1) के अन्तर्गत नगर पंचायत एट जनपद जालौन ने अपनी सीमा में भवन निर्माण उपविधि का पांडुलेख सर्व साधारण को सूचनार्थ उन व्यक्तियों से अपील/सुझाव जिन पर उसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। जिसको हिन्दुस्तान समाचार-पत्र व दैनिक जागरण सामाचार-पत्र में दिनांक 03 अगस्त, 2023 में प्रकाशन करायी गयी, जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। निकाय बोर्ड बैठक दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 को सर्व सम्मति से भवन निर्माण की उपविधि का गजट प्रकाशन हेतु सहमति प्रदान की गयी। अतः नगर पंचायत एट जिला जालौन उक्त उपविधि का प्रकाशन अपनी सीमा के अंतर्गत समस्त भवन निर्माणों पर कर उपविधि प्रकाशित की जाती है। जो गजट मुद्रण के दिनांक से प्रभावी होगी।

भवन निर्माण उपविधि-2023

1—**शीर्षक**—यह उपविधि नगर पंचायत एट, जनपद-जालौन भवन निर्माण उपविधि वर्ष-2023 कहलाएगी।

2—**प्रकृति**—यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत एट, जनपद-जालौन में प्रभावी रहेगी।

3—**परिभाषाएँ**—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में—

1—“**अधिनियम**” का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-संख्या-2, 1916 से है।

2—“अधिशाली अधलारी” का तात्पर्य नगर पंचायत ँट जनपद- जालौन के अधिशाली अधलारी से है।

3—“बोर्ड/समिति” का तात्पर्य नगर पंचायत ँट जनपद-जालौन के बोर्ड/समिति से है।

4—“अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत ँट जनपद-जालौन के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

5—“नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत ँट जनपद-जालौन से है।

6—“नगर पंचायत की सीमाओं” का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

7—भूमि/भवन से तात्पर्य—नगर पंचायत ँट, जनपद जालौन की सीमा में भूमि/भवन से है।

व्यवसाय भवन—जिस भवन में किसी भी प्रकार का व्यवसाय होता हो।

गोदाम—जिस भवन में क्रय या विक्रय के लिए किसी भी प्रकार का माल एकत्रित किया जाता हो तथा रखा जाता हो।

रिहायशी भवन—जिस भवन में कोई परिवार रहता हो या परिवार के रहने योग्य हो।

सामाजिक भवन—जो पूजा या प्रार्थना के लिए प्रयोग होता हो। जिसकी लम्बाई 5x5 मीटर से कम न हो।

सरकारी भवन—जो किसी भी सरकारी कार्यालय के रूप में अस्पताल, विश्राम गृह, स्कूल, पुस्ताकालय, वाचनालय या अन्य किसी शासकीय प्रयोग में आता हो।

हाल—भवन के अन्दर या बाहर वह बड़ा कमरा जो सामुहिक प्रयोग के लिये बनाया गया हो जिसकी लम्बाई 5x5 मीटर से कम न हो।

कमरा—भवन का वह कमरा होगा जो सोने, बैठने व अन्य किसी प्रकार के कार्यों में प्रयोग होता हो जिसकी नाप कम से कम 4x3 मीटर हो।

स्टोर—बड़ा कमरा जिसमें गृहस्थी का सामान एकत्रित किया जाता हो, जिसकी नाप कम से कम 3x3 मीटर हो।

रसोई—जो केवल खाना बनाने के प्रयोग में आता हो तथा उसकी नाम 4x2.5 मीटर हो।

बरामदा—भवन का वह बाहरी भाग जो केवल पिलर पर छाया गया हो, और आगे बन्द न होता हो।

शौचालय—जो शौच के लिये प्रयोग होता हो।

आवाक—जिसके द्वारा मकानों के बीच का पानी सरकारी नाली में प्रवेश करता हो और दोनों नजदीकी मकानों की रोशनी की सुविधा हो। चौड़ाई एक मीटर हो।

वेंटीलेटर—कमरा बंद हो जाने के बाद जिससे स्वच्छ हवा का प्रवेश होता रहे और जो दरवाजे की ऊचाई से अलग होगा।

छज्जा—(पाण्डलर) व ऊपरी भाग जो धूप व पानी रोकने के लिए छत के लेबिल पर बाहर निकाला गया हो।

छज्जी—केवल खिडकी व दरवाजो पर ढकाव के रूप में निकाली गई हो।

जंगला—जो लोहे की सरिया द्वारा बंद हो तथा जिसके द्वारा निकासी न होती हो।

खिड़की—वह स्थान जिसके द्वारा दो कमरे मिल सकते हो या हवा आदि के लिए मेन रास्ते पर खुलती हो।

ओरी भवन—वह हिस्सा जिसके द्वारा धुलाई इत्यादि का पानी कमरे से बाहर निकलता हो या अन्य किसी भी प्रकार का पानी नाली में आता हो।

फर्श—भवन का वह ऊपरी भाग जो समतल हो।

छत—भवन का वह ऊपरी भाग जिससे कमरा इत्यादि छत के भाग से ढका हुआ हो चाहे वह टीन, लकड़ी, ईट, पत्थर, लेन्टर वह अन्य किसी पदार्थ से बना हुआ हो।

अलमारी—कमरे का वह भाग जो दीवार में फिक्स किये जाने के बाद कोई सामान रखने के लिए इस्तेमाल में आता हो।

अंगेठी—जो दीवार में आगे को निकली हुई हो और नीचे का स्थान बाकी हो।

वाटिका—भवन का वह खुला भाग, जिसमें साग-भाजी, फुलवाडी लगायी जाती हो तथा बैठने-उठने के काम में प्रयोग किया जाता हो।

स्टोरी का अर्थ—भवन का वह भाग जो छत के ऊपर और नीचे की छत से मिलता है।

ग्राउण्ड स्टोरी का अर्थ—भवन का वह भाग जो वाहर से प्रवेश पर आता है और जब इस प्रकार की दो सतह हो नीचली सतह ग्राउण्ड स्टोरी कहलायेगी।

हाफ स्टोरी का अर्थ—वह स्थान जो ढालू क्षेत्र के नीचे हो तथा छत को विभाजित करने वाली रेखा हो दीवार का क्षेत्र तीन फीट से अधिक ऊपरी छत की सतह से कम न हो। जिसमें सतह को दो तिहाई से अधिक प्रयोग न हो वह हाफ स्टोरी तथा जो कि स्वतंत्र रूप से पूर्ण रूपेण रहने के योग्य हो फुल स्टोरी कहलायेगी।

निर्माण का अर्थ—पहली बार भवन का निर्माण या मौजूदा भवन के गिराने पर नए नक्शे के अनुसार पुनः निर्माण करना है।

चिमनी का अर्थ—जिसमें से होकर भवन का धुआँ आदि बाहर जाता हो।

अतिरिक्त भवन का अर्थ—एक छोटा भवन मुख्य भवन का एक भाग जिसका प्रयोग आकस्मिक रूप से मुख्य भवन के साथ हो।

घिरा मार्ग का अर्थ—जमीन का वह भाग जो नीव भरने के बाद तुरन्त घेर लिया गया हो लेकिन इसमें निम्न भाग नहीं सम्मिलित है।

रहना का अर्थ—भवन या उसका भाग जो पूर्णतयः या मुख्यतः रहने के लिये बनाया गया हो।

जन चौड़ाई का अर्थ—वह भवन से है जो साधारण कभी कभी चर्च, चौपाल, मंदिर, मस्जिद या जनता के पूजा के स्थान, कालेज, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, जन मनोरंजन गृह, जनता के लिये हाल, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेन्ट प्रयोग होने वाली जगह हो, या प्रयोग में लाई जाने वाली हो।

भौतिक परिवर्तन

(क) किसी भवन के किसी भाग को रहने योग्य भवन में बदलना जो पहले से या वर्तमान स्थिति में व्यक्तियों के रहने योग्य न रहा हो।

किसी भवन के ढांचे में परिवर्तन—पूजा गृह या पवित्र स्थान बनवाने के लिये जो कि इस काम के लिये मूलतः न बनवाया गया हो।

भवन की दीवारों के बीच खुले स्थान को ढकना या छत लगाना जहाँ तक ढाँचे का सम्बन्ध है इसी प्रकार स्थान ढकने या छत बनाने से है।

किसी भवन को स्टाल, दुकान, गोदाम में परिवर्तन करने के लिये जो इस काम के लिये मूलतः ना बनवाया गया हो।

किसी भवन का परिवर्तन करना या मरम्मत करना जबकि वह फ्रेंस बिल्डिंग न हो जिसमें बाहरी या विभाजित करने वाली दीवार को हटाया या पुनः निर्माण करना या कोई दीवार जो छत को रोकती हो नीव की सीमा के ऊपर आधार मजबूत बनाना होगा।

नगरीय भवन निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति 2023 नियमावली

1— यह कि नगर पंचायत एट, जनपद जालौन की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत एट, जनपद जालौन से भवन के मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त ही भवन निर्माण करायेगा।

2— नगर पंचायत एट, जनपद जालौन से स्वीकृति लेने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी होगी।

(अ) प्रार्थी को स्वीकृति चाहने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि 2.00 रु0 की कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर पर होगी।

(ब) इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी को स्वीकृति हेतु मानचित्र मय सीमा के प्रस्तुत करने होंगे। इन मानचित्र में पूर्ण विवरण दिया जायेगा तथा यह भी दर्शाया जायेगा कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दशा है और भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

(स) प्रार्थी इस मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहाँ निर्माण कार्य कराना चाहता है, उसकी अपनी है ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। मानचित्र में भू-खण्ड की चौहद्दी के साथ-साथ भू-खण्ड के चारों ओर के भवन स्वामियों के नाम मानचित्र में दर्शाने अनिवार्य होंगे।

(द) प्रार्थना-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुए वह स्पष्ट करेगा कि भवन की मरम्मत या फेर बदल या ऊपरी भाग का पूर्ण नव निर्माण करना चाहता है।

(य) जिस (ड्राफ्ट मैन) से नक्शा बनवायेगा उसी से उस भवन का अनुमानित स्टीमेट भी प्रस्तुत करेगा।

(र) नक्शे ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिन्ट पर होंगे और एक तीसरा नक्शा जो नगर पंचायत एट, जनपद-जालौन में रखा जायेगा वह ट्रेसिंग पेपर पर होगा।

(ल) प्रार्थी प्रार्थना-पत्र के साथ लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

3—कोई भी भवन निर्माण सरकारी सड़क (पी0डब्लू0डी विभाग/अन्य विभाग के जारी किराईटएरिया के अनुसार) भूमि को छोड़कर किया जायेगा तथा (तंग) गलियों में नाली के बाहरी किनारे से 80 सेमी0 भूमि छोड़कर निर्माण किया जायेगा।

भवन निर्माण—

(अ) प्रत्येक भवन का निर्माण करते समय यह विशेष ध्यान रखा जायेगा कि भवन में आंगन या वाटिका के लिए कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग भूमि खाली छोड़ी जाये।

(ब) भवन में इस प्रकार के जंगलो, वेंटीलेटर लगवाना अनिवार्य होगा जिससे धूप तथा हवा का आगमन हो सके।

(स) इस प्रकार का कोई जंगला या खिडकी न लगाई जायेगी, जिससे कि बराबर में रहने वाले को परेशानी हो।

(द) छत का पानी नीचे तक पाइप लाईन द्वारा ही उतारा जायेगा तथा उसकी नाली सरकारी न होने पर स्वयं अपने व्यय से बनानी होगी। यदि वहां पर सरकारी नाली नहीं है तो प्रार्थी को उसके लिए एक सोकपिट अपनी ही भूमि पर निर्माण करवाना होगा।

(त) दो मंजिले पर इस प्रकार कोई शौचालय नहीं बनवाया जायेगा जिसका मलमूत्र पाइप के द्वारा मकान से बाहर होकर नीचे उतरता हो या सड़क पर गंदगी फैलाता हो।

(थ) सरकारी नाली या सड़क के ऊपर जो प्रोजेक्शन किया जायेगा उस पर अन्य किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा तथा नीचे का लेन्टर नाली के किनारे तक ऊपर का नीचे से प्रोजेक्शन से 50 सेमी0 से अधिक नहीं निकाला जायेगा। सड़क पर किसी प्रकार को कोई प्रोजेक्शन नहीं किया जायेगा।

(द) भवन का परनाला गली में किसी भी हालत में नहीं डाला जायेगा जब तक कि उसके पानी की सरकारी नाली पर पहुंचने की पूर्ण व्यवस्था न कर दी गयी हो।

(ध) भवन की सभी नालियों का गंदा पानी भवन स्वामी स्वयं अपनी लागत से पक्की नाली के पाइप के द्वारा नगर पंचायत एट, जनपद जालौन की सार्वजनिक नाली तक पहुँचायेगा, यदि वहाँ पर नाली नहीं है तो वह अपनी निजी भूमि में सोकपिट बनाकर पानी की व्यवस्था करेगा।

(न) वाटिका या चौक में इस प्रकार का कोई गड्ढा नहीं बनायेगा जिससे कि पानी एकत्रित होने या सड़ना हो।

(प) रसोई तथा शौचालय के बीच कम से कम 04 मीटर का फासला अवश्य होगा, शौचालय उत्तर या दक्षिण में इस प्रकार निर्माण करवाया जायेगा कि उसकी बदबू रसोई घर तक न पहुंचे।

स्वीकृति की विधि—

5—जब प्रार्थी मय नक्शों के प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, सर्व प्रथम उसका इन्द्राज रजिस्टर में किया जायेगा। उक्त प्रार्थना-पत्र पर वित्त विभाग की रिपोर्ट ली जायेगी जब रेवन्यू इंस्पेक्टर इस प्रकार की रिपोर्ट देगा कि इस भूमि या भवन का स्वामी हमारे रिकार्ड में नहीं इन्द्राज है जो प्रार्थना-पत्र दे रहा है तथा इस मकान पर नगर पंचायत एट, जनपद जालौन का कोई किसी प्रकार का टैक्स आदि अवशेष नहीं है।

6—कार्यालय की रिपोर्ट के पश्चात यह प्रार्थना पत्र मय नक्शे अधिशासी अधिकारी/सक्षम कर्मचारी का जांच हेतु भेज दिया जायेगा जो कि मौके पर जाकर भूमि तथा प्लॉट का मिलान करेंगे और रिपोर्ट सही पाये जाने पर नक्शे के मुताबिक नियमानुसार निर्माण उचित है, चौक तथा वाटिका ठीक से सुरक्षित छोड़ दी गयी है, रसोई तथा शौचालय की व्यवस्था सही है। स्वास्थ्य के लिहाज से गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है और इस निर्माण की आज्ञा देने में नगर पंचायत एट की किसी प्रकार की सम्पत्ति को कोई हानि नहीं है।

7—इसके पश्चात प्रार्थी को यह अवगत कराया जायेगा कि वह नियमानुसार निर्माण फीस जमा कर दें। निर्माण फीस जमा हो जाने के पश्चात अधिशासी अधिकारी की संस्तुति के बाद बोर्ड के प्रस्ताव एवं अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति दी जाती है तो नक्शा एवं स्वीकृति पत्र अधिशासी अधिकारी के माध्यम से प्रार्थी का भेज दिया जायेगा। इस आज्ञा के पश्चात ही प्रार्थी निर्माण कार्य आरम्भ कर सकता है। निर्माण कार्य आरम्भ करने से 24 घंटे पूर्व नगर पंचायत एट कार्यालय को अवगत करायेगा।

8—यह आज्ञा केवल एक वर्ष के लिए होगी यदि इस निश्चित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो प्रार्थी को कारण स्पष्ट करते हुए पुनः नगर पंचायत एट से अवधि बढ़वाने हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ पूर्व स्वीकृत पत्र प्रस्तुत करेगा और जो पूर्व फीस जमा की जो उसका 1/2 हिस्सा पुनः फीस के रूप में जमा करनी होगी। यह अवधि छह माह से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। इस छह माह की अवधि बढ़ाने के लिये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत एट/सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा। यदि विशेष परिस्थितियों में प्रार्थी इसके पश्चात भी समय चाहता है तो वह प्रार्थना पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

9—जैसे ही भवन का निर्माण होगा वैसे ही प्रार्थी नगर पंचायत एट को अवगत करायेगा तथा नगर पंचायत एट, जालौन से सर्टीफिकेट प्राप्त करेगा। इसके पश्चात ही भवन रहने योग्य माना जायेगा।

10—शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा—

क्र0	भवन/भूखण्ड का प्रकार	क्षेत्रफल	भूमिगत तल शुल्क प्रति वर्गमीटर	भूतल प्रति वर्गफिट	अतिरिक्त तल प्रति वर्गफिट
1	2	3	4	5	6
		वर्गमीटर	रुपये	रुपये	रुपये
1	व्यवसायिक भवन	40 तक	20.00	05.00	03.00
2	व्यवसायिक भवन	40 से ऊपर	30.00	07.00	04.00
3	गोदाम	40 तक	20.00	05.00	03.00
4	गोदाम	40 से ऊपर	40.00	08.00	04.00
5	होटल का विश्रामगृह, वर्कशॉप, फैक्ट्री, कारखाना	40 तक	50.00	10.00	05.00
6	होटल का विश्रामगृह, वर्कशॉप, फैक्ट्री, कारखाना	40 से ऊपर	60.00	12.00	06.00
7	रिहायसी भवन	200 तक	20.00	05.00	03.00
8	रिहायसी भवन	200 के ऊपर 500 तक	30.00	06.00	03.00
9	रिहायसी भवन	500 से ऊपर	30.00	07.00	04.00
10	अन्य बारात घर आदि	15.00 रुपया प्रति वर्ग मीटर			

11—यदि कोई दुकान, रेस्टोरेन्ट या गोदाम का किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, तो उसकी फीस उपरोक्त फीस की $1/2$ होगी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा गिरजाघर, धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल, वाचनालय या अन्य कोई पूजा ग्रह जिसमें किराये आदि के लिये वह निःशुल्क होगा। खाली प्लॉट की यदि बाउण्ड्री ही बनानी है तो उसके लिये मात्र 1,500.00 (एक हजार पांच सौ रु0) फीस देय होगी।

12—निर्माण का प्रार्थना-पत्र आने की तिथि से 90 दिन के अंदर स्वीकृति होना अनिवार्य होगा, यदि बोर्ड को कोई आपत्ति है तो प्रार्थी को अवगत कराया जायेगा, अन्यथा प्रार्थी गुजरने मियाद 90 दिन बोर्ड को एक सूचना प्रस्तुत करेगा। जिसका समय 07 दिन का होगा। इसके पश्चात वह अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा।

13—बोर्ड को यह पूरा अधिकार होगा कि उचित कारण दर्शाते हुए वह किसी भवन निर्माण की आज्ञा न दे।

14—प्रार्थी यदि नक्शा स्वीकृत हो जाने के बाद कोई परिवर्तन करता है तो पुनः दूसरा नक्शा तथा पहला स्वीकृत नक्शा जिस पर आज्ञा प्राप्त हो चुकी है प्रस्तुत करेगा तथा उपरोक्त अंकित फीस का $1/2$ भाग जमा करेगा।

15—स्वीकृत देने के बाद यदि बोर्ड जनहित में उक्त स्वीकृति को रद्द करना उचित समझता है तो पूरे कारण को स्पष्ट करते हुए भूस्वामी को नोटिस दे, और नोटिस देकर आज्ञा को रद्द कर सकता है जिसकी अपील 30 दिन के अन्दर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

16—प्रारम्भ में जिसमें केवल प्लास्टर आदि या छत आदि ढकने के लिए रु0 1,000.00 (एक हजार मात्र) फीस तथा सादे कागज पर प्रार्थना-पत्र देगा, यदि प्रार्थी पुरानी बुनियादों पर भी क्षतिग्रस्त होने के कारण छत बदलना चाहता

है, तो 1,500.00 (एक हजार पांच सौ रुपये) फीस जमा करेगा, यदि नीचे की मंजिल बनी है और प्रार्थी द्वितीय मंजिल बनवाना चाहता है तो उसके लिये उपविधियों में वर्णित पूर्ण प्रक्रिया अपनानी होगी।

17—सडक पर निर्माण मलवा डालने के लिए हर 15 वर्ग मीटर पर 30 दिन के लिये रु0 500.00 मात्र और इससे अधिक 30 दिन के लिये 750.00 रु0 शुल्क देय होगा। इसके लिए नियमानुसार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, कार्य समाप्त कर सडक पर पडा मैटेरियल साफ करायेगा और गडढे आदि भरवायेगा, यदि यातायात में रुकावट होती है तो अधिशासी अधिकारी को यह पूरा अधिकार होगा कि बिना कारण बताये दी गयी आज्ञा रद्द कर दे। तथा जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

18—कोई भी प्रोजेक्शन इस प्रकार निर्माण न किया जायेगा कि जिसका बरसाती पानी पूरे भाग से बहता हो जिसकी निकासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाईप के द्वारा होगी।

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत एट जनपद-जालौन यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0- 2,000/—(दो हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा हो तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है तो रु0-50/—(पचास रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

पूनम,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत एट, जालौन।

कार्यालय नगर पंचायत एट, जालौन उपविधि

11 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 903/न0पं0एट/ठेकेदारी पंजी0/उपविधि/2023-24—उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 298(2) के अर्न्तगत नगर पंचायत एट जनपद जालौन ने अपनी सीमा में समस्त निर्माण कार्यों के लिये ठेकेदारी पंजीकरण उपविधि का पांडुलेख सर्व साधारण को सूचनार्थ उन व्यक्तियों से अपील/सुझाव जिन पर उसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। जिसको कर्मयुग प्रकाश समाचार पत्र व स्पष्ट आवाज सामाचार पत्र में दिनांक 20 जुलाई, 2023 में प्रकाशन करायी गयी, जिसमें नियम समयावधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। निकाय बोर्ड बैठक दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 को सर्व सम्मति से ठेकेदार पंजीकृत की उपविधि का गजट प्रकाशन हेतु सहमति प्रदान की गयी। अतः नगर पंचायत एट जिला जालौन उक्त उपविधि का प्रकाशन अपनी सीमा के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्यों के लिये ठेकेदारी पंजीकरण वाईलॉज उपविधि प्रकाशित की जाती है। जो गजट मुद्रण के दिनांक से प्रभावी होगी।

उपविधि

1—यह उपनियम नगर पंचायत एट जनपद जालौन में निर्माण कार्य कराये जाने हेतु ठेकेदार पंजीकृत नियमावली वर्ष 2023 कहलायेगी।

2—यह उपनियम नगर पंचायत एट जनपद जालौन के समस्त निर्माण कार्यों के ठेकेदारों पर लागू होंगे।

3—परिभाषाएं—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में—

(1) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत एट जनपद जालौन से है।

- (2) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत एट जनपद जालौन के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- (3) प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत एट जनपद जालौन के प्रभारी अधिकारी से है।
- (4) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत एट जनपद जालौन के अधिशासी अधिकारी से है।
- (5) पंजीकृत का तात्पर्य नगर पंचायत एट जनपद जालौन के ठेकेदारी पंजीकरण से है।
- (6) ठेकेदार का तात्पर्य निर्माण कार्य से है।

(7) फीस (शुल्क) का तात्पर्य उस नकद धनराशि से है जो पंजीकृत होने के लिये नगर पंचायत एट जनपद जालौन में ठेकेदार द्वारा जमा की जायेगी।

- (8) वर्ष का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है।

4—नगर पंचायत एट जनपद जालौन के द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के ठेके लेने का हक उस ठेकेदार को होगा जो नगर पंचायत एट जनपद जालौन में पंजीकृत है। इन ठेकेदारों को यह हक होगा कि नगर पंचायत एट जनपद जालौन के अन्य ठेके भी ले सकते हैं।

5—ठेकेदार को पंजीकृत होने के लिये निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अन्य सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।

6—प्रति वर्ष ठेकेदारों को अपना नवीनीकरण कराने के लिये निर्धारित शुल्क जमा करना होगा और नवीनीकरण न कराने पर पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा।

7—नवीनीकरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अप्रैल में ही कराना होगा। बाद में 30 जून तक प्रति माह अतिरिक्त शुल्क जमा कराने पर ही नवीनीकरण किया जायेगा।

8—ठेकेदार का कार्य खराब होने/असंतोषजनक होने पर अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह पंजीकरण तुरन्त निरस्त कर दें। अथवा नवीनीकरण न करें।

9—पंजीकरण करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा। अनुमोदन अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से कराया जायेगा।

10—प्रत्येक वर्ष 30 जून तक नवीनीकरण न कराने पर ठेकेदार को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। उक्त तिथि के बाद पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होगा। ठेकेदार को पुनः निर्धारित नया पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा पंजीकरण किया जायेगा।

11—पंजीकरण केवल उसी ठेकेदार का किया जायेगा, जिनका पंजीकरण किसी अन्य संस्था से निरस्त न किया गया हो।

12—पंजीकरण हेतु हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र जो जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेगे, प्रस्तुत करना अनिवार्य है पंजीकरण का नवीनीकरण हेतु प्रत्येक वर्ष उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जायेगें। उनके स्थान पर अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र वैध नहीं माने जायेगे। साथ ही श्रम कार्यालय से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

13—नगर पंचायत एट जनपद जालौन में पूर्व से कार्यरत ठेकेदार जिनकी साख एवं कार्य संतोषजनक न रहा हो उसका पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

14—यदि ठेकेदार अपने कार्य को निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नहीं करता है और नगर पंचायत एट जनपद जालौन द्वारा बार-बार अनुरोध व लिखित आदेश देने पर हीला हवाली करता है जिससे नगर पंचायत एट जालौन की छवि खराब होती है। ऐसी दशा में अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस ठेकेदार का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द करने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

15—यदि ठेकेदार अपने कार्य के द्वारा हिटलरशाही, दादागिरी, मनमानी, अनुशासनहीनता एवं वांछित शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही करें।

16—ठेकेदार का पंजीकरण कराने के बाद ठेका लेने के लिये निम्न प्रकार से धनराशि जो अधिशासी अधिकारी के पद नाम से बंधक होगी का बैंक ड्राफ्ट/नकद/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 संलग्न करना अनिवार्य है। जो नगर पंचायत एट जनपद जालौन के अधिकार में रहेगी। तथा ठेकेदार द्वारा कार्य समाप्त होने पर ठेकेदार उसे वापस करायेगा।

17—ठेकेदार को पंजीकरण में जमानत धनराशि निम्न प्रकार से जमा करनी होगी—

1,00,000.00 (एक लाख मात्र) रुपया तक ठेका लेने वाले ठेकेदार के लिये—	दस हजार रुपये मात्र
1,00,000.00 (एक लाख मात्र) से 5,00,000.00 (पांच लाख मात्र) रुपया तक ठेका लेने वाले ठेकेदार के लिये—	पचास हजार रुपये मात्र
5,00,000.00 (पांच लाख मात्र) से 10,00,000.00 (दस लाख मात्र) रुपया तक ठेका लेने वाले ठेकेदार के लिये—	एक लाख रुपये मात्र
10,00,000.00 (दस लाख मात्र) के ऊपर ठेका लेने वाले ठेकेदार के लिये—	दो लाख रुपये मात्र

18—शासनादेश संख्या-609/नौ-2007-249ज-06, दिनांक 29, अप्रैल, 2007 के बिन्दु संख्या-4 का पालन अपेक्षित होगा। निकाय हित में प्रश्नगत आदेश के बिन्दु प्रभावी (निर्माण कार्य हेतु) रहेंगे।

19—पंजीकरण हेतु उन्ही ठेकेदारों को सम्मिलित किया जायेगा। जो इस उपनियम के लागू होने की सभी शर्तों को पूरी करेगा अन्यथा एट नगर पंचायत जनपद जालौन की पंजीकृत सूची में नहीं रह पायेगा।

शुल्क

- (1) पंजीकरण शुल्क 25,000.00 (पच्चीस हजार मात्र) होगी जो कभी भी ठेकेदार को वापस देय नहीं होगी।
- (2) पंजीकरण का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क प्रति ठेकेदार रुपया दस हजार मात्र।
- (3) पंजीकरण का नवीनीकरण विलम्ब शुल्क एक हजार रुपया मात्र (प्रति माह) होगा जो 30 जून तक होगा और अप्रैल माह भी शामिल किया जायेगा, तथा नवीनीकरण शुल्क के अतिरिक्त देना होगा।
- (4) विशेष परिस्थिति में पंजीकरण का नवीनीकरण शुल्क दो गुना अर्थात् दो हजार प्रति ठेकेदार देय होगा।

पूनम,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत एट, जालौन।

कार्यालय नगर पंचायत कुमारगंज, अयोध्या

उपविधि

10 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 09/न0प0कु0/2प्रति0-उपविधि/2023-24—नगर पंचायत कुमारगंज की मा0 सदन की बैठक दिनांक 14 जून, 2023 के प्रस्ताव संख्या-07 के क्रम में नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या-2,1916) की धारा-128 (1) के उपखण्ड (13 ख) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत कुमारगंज अयोध्या ने अपनी सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर कर उगाहने हेतु नियमावली बनायी गयी है। जिसे उक्त ऐक्ट की धारा-131(3) के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से कार्यालय-पत्र संख्या-71 दिनांक 24 अगस्त, 2023 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन कराया गया है। जो हिन्दुस्तान व जनसंदेश समाचार-पत्र में

प्रकाशित है। प्रकाशन के उपरांत 30 दिवस के भीतर आपत्ति/सुझाव मॉंगा गया था। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है। तदोपरांत उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया है। उक्तानुसार उपविधि गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी, जो निम्नवत् है—

नियमावली

1—संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ प्रवृत्ति—

(1) यह नियमावली नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली कहलायेगी।

(2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी, जब से नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाया जाये।

(3) यह नगर में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषाएं—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) से है।

(ख) “नगर” का तात्पर्य नगर पंचायत कुमारगंज से है।

(ग) “शुल्क” का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट-1899 (एक्ट संख्या 2, सन् 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) “इण्डियन स्टाम्प एक्ट” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899) से है।

(ङ) “नगर पालिका/नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत कुमारगंज अयोध्या से है।

(च) “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत कुमारगंज के अधिशाली अधिकारी से है।

(छ) “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत कुमारगंज के अध्यक्ष अथवा प्रशासक से है।

(ज) “कर” का तात्पर्य अधिनियम की धारा-128 की उपधारा (1) के खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3—नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

4—कर के लेखे रखना—निबंधक अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक-पृथक लेखे रखेगा, जिसमें वह शुल्क व कर दिखायेगा।

5—निबंधन अधिकारी, जो दिवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करें और इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट-1908 (एक्ट संख्या 16, 1908) की धारा-89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या-1 में नत्थी करें। राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेंगे।

6—निबंधन अधिकारी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक, पृथक तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूली की गयी धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबंधक को उपयुक्त प्रत्येक महीने के पाँचवें दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

7—(1) नगर पंचायत कुमारगंज की ओर से उगाही कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जावें, काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत कुमारगंज को लौटा दी जायेगी, प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कुमारगंज अयोध्या प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद को फाइनेंशियल हैण्ड बुक खण्ड-5 भाग के प्रपत्र संख्या-19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी, जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदिन का धनराशि प्राप्त करेगा।

(2) पालिका निबन्धन और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगा, जो नगर पंचायत के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

(3) **कर लगाने की प्रक्रिया**—उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका/नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी।

1—अब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिये प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प-एक्ट की धारा-27 में निर्दिष्ट ब्यौरे—

निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक-पृथक दिये गये हैं—

(क) नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति, और

(ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

2—यदि ऐसे ब्यौरे दस्तावेज में पृथक-पृथक व दिये गये हो तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा-128क की उपधारा (4) धारा नगर पालिकाओं पर यथा प्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

8—अभिलेखों का निरीक्षण—अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

9—इस उप नियमावली की उपरोक्त किसी भी उपधारा में किसी प्रकार का संशोधन का अधिकार अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष में निहित होगा।

शास्ति

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) के द्वारा प्राप्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत कुमारगंज, जनपद-अयोध्या यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपबंधों का उल्लंघन अर्थदण्ड लिया जायेगा, जो रु0 10,000.00 हो सकता है।

विकास सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत कुमारगंज,
अयोध्या।

कार्यालय नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा, अयोध्या

उपविधि

20 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 19/न0पं0भ0/2प्रति0-उपविधि/2023-24-नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा की मा0 सदन की बैठक दिनांक 22 जून, 2023 के प्रस्ताव संख्या-8 के क्रम में नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0एक्ट संख्या-2,1916) की धारा-128 (1) के उपखण्ड (13 ख) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा अयोध्या ने अपनी सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर कर उगाहने हेतु नियमावली बनायी गयी है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 131(3) के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से कार्यालय पत्र संख्या-325/न0पं0भ0/02प्रति0-उपविधि/2023-24 दिनांक 24 अगस्त, 2023 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन कराया गया है। जो हिन्दुस्तान व जनसंदेश समाचार-पत्र में प्रकाशित है। प्रकाशन के उपरांत 30 दिवस के भीतर आपत्ति/सुझाव मॉंगा गया था। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है। तदोपरांत उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया है। उक्तानुसार उपविधि गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी, जो निम्नवत् है—

नियमावली

1—संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ प्रवृत्ति—

1—यह नियमावली नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली कहलायेगी।

2—यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी, जब से नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाया जाये।

3— यह नगर में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होगी।

2— परिभाषाएं—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

क—“अधिनियम” का तात्पर्य संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) से है।

ख—“नगर” का तात्पर्य नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा से है।

ग—“शुल्क” का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, सन् 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है।

घ—“इण्डियन स्टाम्प एक्ट” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899) से है।

ङ—“नगर पालिका/नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा अयोध्या से है।

च—“अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा के अधिशाली अधिकारी से है।

छ—“अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा के अध्यक्ष अथवा प्रशासक से है।

ज—“कर” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3—नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

4—कर के लेखे रखना—निबंधक अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक-पृथक लेखे रखेगा, जिसमें वह शुल्क व कर दिखायेगा।

5—निबंधन अधिकारी, जो दिवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करें और इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (एक्ट संख्या 16, 1908) की धारा 89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करें। राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेंगे।

6—निबंधन अधिकारी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, और अक्टूबर, के महीनों में पृथक, पृथक तिमाही विवरण—पत्र तैयार करेगा, जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूली की गयी धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबंधक को उपयुक्त प्रत्येक महीने के पॉचवें दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

7—(1)—नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा की ओर से उगाही कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जावें, काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा को लौटा दी जायेगी, प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा अयोध्या प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद को फाइनेंशियल हैण्ड बुक खण्ड-5 भाग के प्रपत्र संख्या-19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी, जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान का धनराशि प्राप्त करेगा।

(2)—पालिका निबंधन और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगा, जो नगर पंचायत के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

(3)—कर लगाने की प्रक्रिया—उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका/नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी।

1—अब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिये प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-27 में निर्दिष्ट ब्यौरे—

निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक-पृथक दिये गये हैं—

क—नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति, और

ख—नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

2—यदि ऐसे ब्यौरे दस्तावेज में पृथक-पृथक व दिये गये हो तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा-128 क की उपधारा (4) धारा नगर पालिकाओं पर यथा प्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

8—अभिलेखों का निरीक्षण—अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

9—इस उप नियमावली की उपरोक्त किसी भी उपधारा में किसी प्रकार का संशोधन का अधिकार अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष में निहित होगा।

शास्ति

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) के द्वारा प्राप्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा जनपद-अयोध्या यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपबंधों का उल्लंघन अर्थदण्ड लिया जायेगा, जो रु0 10,000.00 हो सकता है।

मो0 राशिद,

अध्यक्ष,

नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा,

अयोध्या।

सूचना

सूचना फर्म मेसर्स शिवालिक इन्जीनियरिंग, 61-ए करौल, आर्यकन्या इण्टर कालेज के पीछे इटावा, के पार्टनर सुनील शर्मा पुत्र श्री बलदेव प्रसाद शर्मा व ज्योति शर्मा पुत्री स्व0 बाबादास शर्मा निवासिनी 5-जी टी0सी0एल0 कालोनी सरोजनी नगर लखनऊ को दिनांक 31 मार्च, 2023 से स्वेच्छा से रिटायर्ड हो गये हैं। अब उक्त फर्म में मात्र दो पार्टनर अरुण कुमार शर्मा पुत्र श्री बलदेव प्रसाद शर्मा व श्रीमती सुनीता शर्मा पुत्री श्री डी0पी0 प्रभाकर निवासी 61-ए करौल आर्यकन्या इण्टर कालेज के पीछे इटावा ही पार्टनर हैं।

अरुण कुमार शर्मा (पार्टनर),
फर्म मेसर्स शिवालिक,
इन्जीनियरिंग, 61-ए करौल, इटावा।

उपरोक्त फर्म में साझेदार श्रीमती कुमकुम मित्तल पत्नी श्री धनेश कुमार मित्तल, श्रीमती नेहा अग्रवाल पत्नी श्री तनुज अग्रवाल, श्रीमती नीता मित्तल पत्नी श्री राजेश कुमार मित्तल, श्रीमती निधि अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश कुमार अग्रवाल सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 28 जनवरी, 2022 को संचालन की थी दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से श्रीमती निधि अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश कुमार अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गयी है फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नहीं है अब फर्म को श्रीमती कुमकुम मित्तल, श्रीमती नेहा अग्रवाल, श्रीमती नीता मित्तल संचालित करेंगे।

कुमकुम मित्तल
साझेदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वास्ते- फर्म मेसर्स मिर्जा प्रोजेक्ट्स 14/6 सिविल लाईन्स कानपुर नगर की साझीदारी दिनांक 19 जून, 2007 को दिनांक 12 सितम्बर, 2023 से विघटित कर दिया गया है।

फर्म के विघटन के समय साझीदारी की स्थिति निम्नवत है:-

1. श्री राशिद अहमद मिर्जा पुत्र स्व0 इरशाद मिर्जा निवासी 7/77 सी तिलक नगर, कानपुर।
2. श्री शाहिद अहमद मिर्जा पुत्र स्व0 इरशाद मिर्जा निवासी 7/77 सी तिलक नगर, कानपुर।
3. श्री तौसीफ अहमद मिर्जा पुत्र स्व0 इरशाद मिर्जा निवासी 7/21 पर्वती बागला रोड, कानपुर।
4. श्री तसनीफ अहमद मिर्जा पुत्र स्व0 इरशाद मिर्जा निवासी 7/21 पर्वती बागला रोड, कानपुर।
5. श्री शूजा मिर्जा पुत्र श्री राशिद अहमद मिर्जा निवासी 7/77 सी तिलक नगर, कानपुर।

तसनीफ अहमद मिर्जा,
साझीदार,
मेसर्स मिर्जा प्रोजेक्ट्स,
14/6 सिविल लाईन्स कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मे0 केशव पेपर्स, नियर होटल राधा अशोक सरस्वती कुण्ड मथुरा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म ज्ञान इम्पैक्स, के0ई0-63, कावेरी कुंज फेस-2, कमला नगर, आगरा पर स्थित है। उपरोक्त फर्म का पुराना पता जो कि के0ई0-63, कावेरी कुंज फेस-2, कमला नगर, आगरा था का पता परिवर्तित कर नया पता मधू नगर चौराहा, निकट पराग डेरी, आगरा कर लिया गया है। उपरोक्त फर्म में श्री कैलाश चन्द्र जैन पुत्र श्री मुन्ना लाल जैन निवासी- चौबेजी का फाटक, किनारी बाजार, आगरा और श्रीमती अनीता जैन पत्नी श्री कैलाश चन्द्र जैन निवासी-के0ई0-63 कावेरी, कुंज फेस-2, कमला नगर, आगरा साझेदार थे। श्री अनिकेत अग्रवाल पुत्र श्री उमेश कुमार अग्रवाल निवासी-38ए/440/पी-8, सेवला सराय, विरमा नगर, नई चुंगी आगरा, श्री अमन बंसल पुत्र श्री मनोज कुमार बंसल निवासी-14/56, मंडी सैयद खां, हरीपर्वत, आगरा, श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री दिलीप कुमार अग्रवाल निवासी-2/364, नामनेर प्रताप पुरा, आगरा, श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री रमनलाल अग्रवाल निवासी-14, बंसत बिहार, निकट महाराजा अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर, आगरा और श्री मनोज अग्रवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल निवासी-35, कावेरी कुंज, कावेरी मंदिर के सामने, कमला नगर, आगरा दिनांक 06 नवम्बर, 2023 से उक्त फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में श्री कैलाश चन्द्र जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अनिकेत अग्रवाल, श्री अमन बंसल, श्री आशीष अग्रवाल, श्री विकास अग्रवाल और श्री मनोज अग्रवाल साझेदार हैं।

कैलाश चन्द्र जैन।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 श्री गणेश आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, गदौली खुर्द, पो0 देवरी इरादत नगर रोड, तह0 फतेहाबाद जिला आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री भीकम सिंह त्यागी, श्री रामचरण त्यागी निवासीगण पो0 इरादत नगर तह0 फतेहाबाद जिला आगरा हम दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 10 मई, 2006 को संचालन की थी। दिनांक 29 अप्रैल, 2024 से श्री लक्ष्मीकान्त त्यागी, श्री शिवकान्त त्यागी फर्म में साझेदार हो गये हैं। दिनांक 29 अप्रैल, 2024 से श्री रामचरण त्यागी फर्म से पृथक हो गये हैं। अब फर्म को श्री भीकम सिंह त्यागी, श्री लक्ष्मीकान्त त्यागी, श्री शिवकान्त त्यागी हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

भीकम सिंह त्यागी
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शपथकर्ता के पुत्र का सही नाम कृष्णा शुक्ला (KRISHNA SHUKLA) पुत्र विनोद कुमार शुक्ल (VINOD KUMAR SHUKLA) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश शपथकर्ता के आधार कार्ड सं0 3857 6586 3732 में रुद्र प्रकाश शुक्ल अंकित हो गया है, जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में शपथकर्ता के पुत्र को कृष्णा शुक्ला (KRISHNA SHUKLA) पुत्र विनोद कुमार शुक्ल (VINOD KUMAR SHUKLA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

विनोद कुमार शुक्ल,
243 परानीपुर पोस्ट परानीपुर,
मेजा, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व त्रिपाठी (ATHARV TRIPATHI) है, जो कि उनके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे

पुत्र के आधार कार्ड सं0- 9589 8119 4033 में शगुन त्रिपाठी (SHAGUN TRIPATHI) अंकित हो गया है, जो उसका घरेलू नाम है। उपरोक्त दोनो नाम मेरे पुत्र का ही है। भविष्य में मेरे पुत्र को अथर्व त्रिपाठी (ATHARV TRIPATHI) पुत्र सतीश कुमार त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

स्थाई पता— ग्राम जददूपुर, कछवां रोड, मिर्जामुराद, वाराणसी, उ0प्र0, हाल पता— फायर स्टेशन नैनी, प्रयागराज।

सतीश कुमार त्रिपाठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिक सिंह पुत्र शैलेन्द्र कुमार सिंह है, जो उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0- 3187 3597 2679 में अनमोल सिंह अंकित हो गया है, जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को कार्तिक सिंह पुत्र शैलेन्द्र कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

शैलेन्द्र कुमार सिंह,
पुत्र सच्चिदानन्द सिंह,
ग्राम व पो0 संवरा, थाना व तहसील रसड़ा,
जनपद बलिया।

NOTICE

This is to inform publically that in my class 10th Marksheet of CBSE Board, Roll no. 23271469 passed in the year 2023, my mother name is wrongly entered as Suman Devi where as my mother correct name is Suman Chaturvedi and the correct mother name should be entered in my marksheet.

Indul Chaturvedi,
S/o Rahul Chaturvedi,
Katra Bazar, Katra,
Koirana Bhadohi.